W अपने उस पुराने निर्णय को पुष्ट किया हैं। कर्नाटक की सरकार जहां से स्वयं मिसेज मारगेट आल्वा हैं कर्नाटक की सरकार को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता, आप जिस मर्जी के लिए आरक्षण करिए लेकिन कुल मिलाकर 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि 50 फीसदी की सीमा में एस. सी./ एस टी का आरक्षण साढ़े बाइस प्रतिशत हैं, उसमें भी एस.टी. का आरक्षण साढ़े सात प्रतिशत है तथा एस.सी. का आरक्षण केवल 15 प्रतिशत हैं। अगर क्रिश्रियन दलित के नाम पर एक वर्ग को इसमें जोड़ा जाता है तो उसी 15 प्रतिशत के हिस्सेदार वे होंगे जो 15 प्रतिशत कि हिसेदार वे होंगे जो 15 प्रतिशत आलरेडी हरिजनों को मिला हुआ हैं। इससे पहले भी जब एक्स सर्विससेज के लिए आरक्षण रखा गया, विक्लांगों के लिए आरक्षण रखा गया तो उनमें जो एस.सी थे उनको इस 15 प्रतिशत के अगेंस्ट जोड़ दिया गया। अब अगर एक अलग वर्ग और वह वर्ग भी कौन सा, जो इन हिन्दू हरिजनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पढ़ा – लिखा है, कान्वेंट एजुकेटिड है, अगर उनको इस 15 प्रतिशत का, जिनको पहले ही अपनी आबादी से कम हिस्सा मिला हुआ है। इसलिए , उपसभाध्यक्ष जी , मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह मांग हरिजनों को मिले हुए हिस्से में से और ज्यादा उनके हिस्सा कम करने की मांग है, आलरेडी हरिजनों का जो उपेक्षित वर्ग है, उन पर अन्याय करने की मांग है। इसलिए ये दो प्रमुख कारण है, कारण तो और भी हैं लेकिन ये दो प्रमुख कारण हैं ...(**व्यवधान**) ....

**उपसभाध्यक्ष ( श्री सतीश अग्रवाल )** इसमें कोई डिबेट नहीं हो रही हैं, समाप्त कीजिए।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिनके कारण से मेरा दल आरक्षण की इस मांग विरोध करता है और इस बात को मैं दर्ज कराना चाहती हूं।

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : उपसभाध्यक्ष जी।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Mr. Nilotpal Basu, you have not sought permission. If you are allowed to speak, then I will also speak. ...*(Interruptions)*...

**उपसभाध्यक्ष ( श्री सतीश अग्रवाल) :** श्रीमती सरला माहेश्वरी जी, आपका एसोसिएशन मैंने लिख दिया हैं। ...(व्यवधान) ...

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : इसमें अलग तरह के विचार भी आए हैं और एक बहसनुमा रूप दे दिया गया है इसको। इसलिए पहले तो मेरा ...(**व्यवधान**) ...

**उपसभाध्यक्ष ( श्री सतीश अग्रवाल) :** इसलिए मैंने उनको रोक दिया हैं। सुषमा जी को इसलिए रोका है कि इसमें कोई डिबेट नहीं है।

**श्रीमती सरला माहेश्रवरी** : जब पूरी बहस को यहां रूपांतरित किया जा चुका है तब मैं समझती हूं ...(**व्यवधान**) ...

**उपसभाध्यक्ष ( श्री सतीश अग्रवाल) :** दो स्पेशल मेंशन और हैं। अगर वह खत्म हो जाएंगे तो ढाई बजे दूसरा विषय ले लेंगे। राघवजी बहुत इतंजार कर रहे हैं। आपका एसोसिएशन में लिखा देता हूं विद मि. जार्य एंड मि. वायालार रवि ने भी कहा है। आपका भी एसेसिएशन है।

**श्रीमती सरला माहेश्रवरी (पश्चिम बंगाल)** हमारे संविधान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमारा देश एक धर्मनिपेंक्ष राष्ट्र है और धर्मनिपेंक्ष राष्ट्र होने के नाते राज धर्म के नाम पर अपने आर्थिक लाभों के बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा । यह हमारे संविधान निर्मातओं की स्पष्ट समझ थी और इसी स्पष्ट समझ के साथ हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि हमारे संविधान में जो दंलित है, पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं सिर्फ इस कारण से उन्होंने दूसरा धर्म ले लिया हैं। (**व्यवधान**) ... इस कारण राष्ट्र का यह अधिकार नहीं बनता कि वह उनकी जायज मांर्गो की उपेक्षा करें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I also want to associate myself with this Special Mention. I want to say that untouchability was not the criterion for reservation. It is a wrong impression because untouchability is a crime in India today. So, it cannot be a criterion for reservation. Normally, Sir, these are the reservations meant for those Indians who are socially and economically backward and if they change their religion, they do not cease to be Indians. They continue to be Indians. So, it cannot be a bar. So, I fully endorse the views of my hon. friend.

**Acute Shortage of Power in Karnataka**

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the hon. House the problem of acute shortage of power in Karnataka. The power crisis in Kemataka is so acute that

if timely action is not taken by the Centre, Bangalore will become another Calcutta of 1970 and the industies will start going away from Karnataka. Karnataka has never faced such a crisis in the past. The Karnataka Government has almost given up the idea of taking any action. It has no will power to solve the problem. The joke in Karnataka is: "When will the power be there?" The cities and towns are almost in darkness. The industrialists are crying and the State/Government is just watching. The small-scale industries are almost closing down and have no capacity to go in for captive power. People are at a loss to understand why all of a sudden this crisis has arisen. On earlier occasions also, there used to be a failure of monsoon, but such a situation has never arisen in Karnataka. Last year, during the same season, there was no power cut or no power shortage. The Government of India cannot be a silent spectator to the situation. The Central Government should come to the rescue of the people of Karnataka by allotting additional power from the Central Grid to meet the crisis and save Karnataka. Bangalore has been considered as a Silicon Valley of Asia and poised to become the world capital in electronics. The State Government does not seem to be keen to face the situation. I appeal to the Government of India to take urgent steps to provide 500 mega watts of additinal power to Karnataka immediately. I also urge upon the Government of India to clear all the pending power projects in Karnataka and expedite the work. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri B.K. Hariprasad. Do you want to associate yourself with it?

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Yes, Sir, I am also associating myself with this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Your association is on record.

**Unprecedented Power Crisis in Madhya Pradesh**

**उपसभाध्यक्ष ( श्री सतीश अग्रवाल ) :** श्री राघवजी, जल्दी खत्म करिए। बहुत टाइम हो गया है।

**श्री राजवधी जी (मध्य प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने से अभूतपूर्व बिजली संकट है। कारखाने लगभग बंद पड़े हैं। 25 प्रतिशत यूनिटों में उत्पादन नहीं हो रहा है। छोटे छोटे उद्यमियों को अपना काम बंद करना पड़ है। आटा चक्कियां, वेल्डिंग मशीनें सब बदं है, पीने के पानी की व्यवस्था खत्म हो चुकी है क्योंकि वह भी बिजली पर आधरित है। अस्पतालों मे आपरेशन तक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पर बिजली नहीं मिल पा रही हैं। सरकार यह कहती है कि हम सिंचाई के लिए बिजली दे रहे हैं इसलिए शहरों में बिजली बंद है। पिछले एक महीने से सिंचाई के लिए गांवों में बिजली नहीं जा रही हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां दो दो महीने तक बिजली नही पहुंची हैं। जहां बिजली है वहां दिन में दो घंटे भी बिजली नहीं रहती है। पलेवा नहीं हो पर रहा है जिसकी वजह से बोनी नहीं हो पा रही हैं और इसके कारण से खेती भी प्रभावित हो रही है और इस तरह से नगरों और गांवों मे दोनों जगह बिजली का बहुत संकट हो गया है(समय की घंटी ) में दो मिनट और लूंगा।

**उपसभाध्यक्ष ( श्री सतीश अग्रवाल ) :** नहीं , दो मिनट नहीं। आपकी चीज रिकार्ड पर आ गयी है। इतना ही काफी है।

**श्री राघवजी :** इसके लिए पूर्व मुख्य मंत्री ने भी तीन दिन के लिए धरना दिया है। कांग्रेस के एक मुख्य मंत्री ने एक आरोप लगाया है कि यह सब कुप्रबंध के कारण है और जानबूझकर जो 22 परियोजनाएं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है। उनको वैलिड ठहराने के लिए के लिए उनका काज मजबूत करने के लिए वतैमान व्यवस्था अस्त व्यसथ की जा रही है। इसके कारण बिजली संकट पैदा हुआ है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि केन्द्र शासन जल्दी से जल्दी इसमें हस्तक्षेप करें ताकि मध्य प्रदेश की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और मध्य प्रदेश को विद्युत प्राप्त हो सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Now, we take up the Private members' business, but before we do that, I would request